बिजनेस स्टैंडर्ड, भोपाल
27 MAR 2017

गेहूं खरीद व्यवस्था से खुश हैं किसान!

आनन्द जाट
भोपाल, 26 मार्च

मप्र सरकार किसानों से 1,385 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है। राज्य में गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई ई उपार्जन व्यवस्था किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है

राज्य के सीहोर जिले के गांव बोरखेड़ा के किसान केवलराम वर्मा इस बार गेहूं बिक्री की प्रक्रिया से खुश है। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के काम को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई ई उपार्जन व्यवस्था किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और केवलराम भी इन्हीं किसानों में से एक है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मार्च से अब तक राज्य सरकार 44 हजार किसानों से 3.25 लाख टन गेहूं की खरीद कर चुकी है। राज्य सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य पर 100 रुपये का बोनस दे रही है। इस प्रकार सरकार किसानों से 1,385 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदारी कर रही है। वहीं मंडियों में गेहूं के भाव 1150 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर है। गेहूं बिक्री के लिए इस बार राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच 11,72,712 किसानों ने पंजीकरण कराया था। इसके बाद 28 फरवरी से 4 मार्च के बीच छूटे हुए किसानों का पंजीकरण फिर किया गया।

पिछले साल भी राज्य सरकार ने गेहूं की फसल पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया था। जबकि पड़ोसी राज्यों में केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर ही गेहूं की खरीदारी की गई थी। इससे अन्य राज्यों का गेहूं भी मध्य प्रदेश में बेचे जाने के आरोप राज्य सरकार पर लगे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री पारसचंद जैन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'सरकार ने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में पहल की है। इस बार राज्य में गेहूं खरीद का काम तेज गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर से गेहूं बिक्री करने वाले किसानों के पंजीयन का काम शुरू किया गया था। वहीं 15 मार्च से शुरू हुई गेहूं खरीद में अब तक 3.25 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।'

गेहूं खरीदने के बाद किसानों को 7 दिन के अंदर उनकी उपज का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेशभर के 2320 खरीद केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीदने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, 920 केंद्रों के माध्यम से ही फिलहाल खरीद की जा रही है। जैन ने कहा, 'पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 2320 खरीद केंद्र बनाए गए हैं लेकिन उपज के अभाव में सिर्फ 920 केंद्र ही फिलहाल शुरू किए गए हैं। बाकी क्षेत्रों में उपज आने के बाद खरीद शुरू की जाएगी। 15 मार्च से अब तक 450 करोड़ रुपये का भुगतान 44,000 किसानों को किया जा चुका है।'